कोरोना संकट में आर्थिक मंदी से उबरने के उपाय (एक शोध अध्ययन)

डॉ. आनंद तिवारी
विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

कोरोना संकट ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब तक समूचे विश्व में तीन आर्थिक मँदियाँ आ चुकी हैं वर्ष 1929 की विश्वमंदी शेयर बाजार के कारण हुई, वर्ष 1990 की मंदी तेल कीमतों के कारण हुई, वर्ष 1908 की मंदी बाजार अर्थव्यवस्था के कारण हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी घरेलू बचत तथा सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण इन मंदियों का सामना कर सकी। कोविड-19 जिन परिस्थितियों में जन्मा निश्चित रूप से वे परिस्थितियाँ अप्रत्याशित रहीं इसलिए इस अर्थिक सकंट का समाधान न तो पूंजीवाद में निहित है और न ही समाजवाद, साम्यवाद, लेनिनवाद या मार्क्सवाद में निहित है। इस अर्थिक सकंट का समाधान केवल गाँधीवादी विचारधारा द्वारा संभव है। आज पुनर्विचार करना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कैसे सुदृढ़ किया जाये? ग्राम कुटीर एवं लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने की महती आवश्यकता है।

मुख्य शब्द - साम्यवाद, लेनिनवाद, अल्पजीवी, एशियाई बैंक ।

कोरोना एक लघु, अल्प जीवी, कमजोर वायरस जो प्रकृति जन्य है या मानव जन्य यह शोध एवं अन्वेषण का विषय है। परन्तु इस वायरस ने यूरोपीय देशों से लेकर एशियाई देशों तक समूची पृथ्वी में मानवीय जीवन के अस्तित्व के संकट के साथ-साथ मनुष्य एवं प्रकृति के संबंधों पर प्रश्न चिन्ह रेखांकित कर दिया है। भयावहता इस तथ्य को लेकर है कि चीन के जिस वुहान शहर से इस वायरस ने जन्म लिया था वहाँ 90 प्रतिशत संक्रमण से स्वस्थ लोगों को फेफड़ों में संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना आज न केवल चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए अपितु समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, राजनैतिज्ञों तथा मनोवैज्ञानिकों के लिए चिंतन का विषय है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को विश्व महामारी घोषित किया है वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे न केवल चिकित्सकीय संकट माना है बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती भी मानता है। दुनिया के तीन लोकतांत्रिक देशों में जिनमें अमेरिका, ब्राजील तथा भारत कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है परन्तु भारत के संदर्भ में सुखद बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट संतोषप्रद है साथ ही मृत्यु दर भी कम है। भारत में यह वायरस अब तक नगरीय क्षेत्रों में फैला है। सोशल डिस्टेंसिग तथा मॉस्क का प्रयोग वायरस को फैलने का कारगर उपाय हो सकता है। आशा की जानी चाहिए कि भारत में इसकी वैक्सीन दिसम्बर माह तक आ जायेगी।

जहाँ तक कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का सवाल है तो यह प्रासंगिक है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई देशों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा है कि कोरोना के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर क्रमशः 5 तथा 2.8 प्रतिशत रहने की आशंका है और यह आर्थिक झटका ऐसे समय में लगा जबकि वित्तीय क्षेत्र के दबाव के कारण अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में थी। सेंटर फॉर इण्डियन एकोनामी के अनुसार कोरोना से पूर्व भारत में रोजगाररत् व्यक्तियों की संख्या 40.4 करोड़ थी जो आज घटकर 28.5 करोड़ रहने की आशंका है।

अध्ययन का विश्लेषण :

भारतीय संदर्भ में कोविड-19 के संबंध में तीन पहलुओं पर विचार करना नितांत आवश्यक है:-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर आबादी वाला असंगठित क्षेत्र, जिसमें दैनिक श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, अनुबंधित श्रमिक, फेरी वाले, सड़क किनारे फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लघु व्यवसायी एवं सेवा प्रदाता जो रोजाना कमाकर अपनी आजीविका चलाते हैं।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विर्निर्माण क्षेत्र में उत्पादन करने वाला वर्ग जो पूंजीगत तथा गैर पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों में संलग्न वर्ग अर्थात व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र।
3. तीसरा ऐसा वर्ग जिसका अर्थव्यवस्था में निर्णायक योगदान रहता है जिसमें लोवर तथा मिडिल लोवर इनकम ग्रुप आता है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कमजोर तथा असंगठित क्षेत्र के लिए मुफ्त राशन, खाद्यान्न, भोजन तथा परिवहन के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों में पलायन करने वाले श्रमिकों को मनरेगा, व श्रम संवृद्धि जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। केन्द्र सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की गई थी परन्तु ये सभी प्रयास अल्पकालिक रहे हैं, आवश्यकता दीर्घ कालिक प्रयासों को अंगीकार करने की है।

निर्वाचन :

अब आवश्यकता इस बात को लेकर है कि भारत की कोरोना संकट के पश्चात् अर्थव्यवस्था की स्थिरता प्रदान करने तथा गतिमान बनाने हेतु कतिपय दीर्घकालिक उपायों को अपनाना होगा। तभी हम कोरोना जैसे संकटकाल को अवसर के रूप में बदल सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण समन्वित एवं समावेशी विकास की दिशा में ला सकते हैं, ऐसे उपायों में पांच उपायों को आत्मसात करना होगा।

1. समूची दुनिया चीन से अपना उत्पाद निर्माण कराने में विश्वास करती है आज दुनिया के तमाम देशों का विश्वास समाप्त हो चुका है यही अवसर है कि हम पश्चिमी देशों को आमंत्रित करें कि हम उनकी आवश्यकता का उत्पादन तैयार करेंगे परन्तु इस हेतु भारत को तीन दिशाओं में कार्य करना होगा, पहला दूरसंचार क्षेत्र तो त्वरित गति देना होगी, विश्व इंटरसेट में हमारी गति काफी धीमी है, हमें अपने वॉयफाय

को दुरुस्त करना होगा, दूसरा कार्य परिवहन क्षेत्र में करना होगा, हवाई यातायात का विकल्प खोजना होगा, साथ ही सड़क तथा जल यातायात की दिशा में आमूल बदलाव लाना होगा। चीन में सड़क तथा जल परिवहन की गति हमारी तुलना में पांच गुना अधिक है, तीसरा विदेशी तथा देशी निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु वैधानिक औपचारिकताओं में कमी करनी होगी, कतिपय कानूनों में संशोधन करने की महती आवश्यकता होगी विशेषकर एम.आर.टी.पी. एक्ट तथा फेमा कानून।

2. भारत को चीन पर निर्भरता समाप्त करना दूसरा कदम होगा, भारत चीन से इलेक्ट्रानिक सामान 45 प्रतिशत, मशीनरी 33 प्रतिशत, आटोमोबाईल्स तथा उर्वरक 25 प्रतिशत, दवायें 65 प्रतिशत तथा मोबाईल एसेसरीज 91 प्रतिशत आयात करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत स्वयं इन वस्तुओं का उत्पाद करे और हम सभी के लिये यह सुखद समाचार है कि भारत की लगभग 22 कंपनियां मोबाईल उत्पादन में आगे आ रही हैं जिनमें 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार की संभावना होगी। फॉक्सकान, पेगाइन, लावा, सेमसंग तथा माइक्रोसाफ्ट जिनमें प्रमुख हैं। आटोमोबाइल्स में मारूति, होंडई, सुजुकी तथा हीरोहोण्डा निर्माण तथा टर्नओवर में अग्रसर हो रही हैं। आज जरूरत इस बात की है कि विदेशी कुशल तकनीकी मानव संसाधन का आयात करें ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों की भांति इनके स्लिक का उपयोग कर निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें।

3. तीसरा कदम पर्यटन क्षेत्र में उठाना होगा, भारत की सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यह देश सदैव से विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र रहा है। आज कोरोना संकट के कारण भारत में वर्ष 2018-19 में 87 मिलियन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। आज धार्मिक तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की है, भारत के कतिपय राज्य उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तरपूर्वी राज्यों में पर्यटन की असीम संभावनायें हैं जिनको विकसित करना होगा, इससे होटल, रेस्टोरेंट तथा परिवहन क्षेत्र में रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही राज्यों को राजस्व भी मिलेगा।

4. लॉकडाउन के कारण महानगरों से गाँवों की ओर लगभग 10 करोड़ श्रमिकों का पलायन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण तथा कृषि अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है इस दिशा में दो उपाय अपनाना होंगे- पहले उपाय के रूप में चूंकि उत्पादन प्रक्रिया उद्योगों में प्रारंभन स्थिति में है, अब शासन व प्रशासन की महती जिम्मेदारी है कि श्रमिकों को विशेषकर कुशल श्रमिकों को सुरक्षित ढंग से महानगरों में प्रवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और आवास की रियायती सुविधा उपलब्ध करायी जाये साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। दूसरे उपाय के रूप में गाँवों में स्थायी रोजगार का सृजन करना नितांत आवश्यक है, दीर्घकालिक उपाय के रूप में पर्यावरण संरक्षण तथा रोजगार सृजन हेतु तालाब, कुएं, बावड़ी की सफाई व शहरीकरण के साथ वृक्षारोपण का कार्य किया जाये, इन कार्यों को सतत रूप में किया जाये ताकि स्थायी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

5. पाँचवे एवं अंतिम उपाय के रूप में ग्रामीण तथा कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु तीन उपायों

को अंगीकार करना होगें : आज पूँजी प्रधान तकनीक के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीक को अंगीकार करना होगा यह तभी संभव होगा जबकि मानसिक श्रम करने वाले मानव संसाधन की भांति शारीरिक श्रम करने वाले मानव संसाधन को महत्व दिया जाये। कृषकों की उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना होगा और न्यूनतम समर्थ मूल्य किसानों को दिलानी सरकार की महती आवश्यकता होगी और ग्राम्य उद्योग, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना होगा।

सारांश :

कोविड-19 को लेकर सबसे बड़ी चिंता आर्थिक मंदी को लेकर है अब तक समग्र विश्व में तीन आर्थिक मंदियाँ आ चुकी हैं। 1929 की मंदी, जो शेयर बाजार के कारण हुई, 1990 की मंदी जो तेल की कीमतों के कारण हुई, 1908 की मंदी परन्तु इन तीनों मंदियों से बाहर आ गया। आर्थिक मंदियों से बाहर अपनी घरेलू बचत तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण आ सका, निश्चित रूप से कोविड-19 जिन परिस्थितियों में जन्मा उनके परिणामों का समाधान किसी आर्थिक सिद्धान्त विचारधारा या मॉडल द्वारा संभव नहीं है याने इस आर्थिक संकट का समाधान न हो, पूंजीवाद में है नहीं, समाजवाद, साम्यवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद में केवल या फासीवाद में इसका समाधान केवल संभव गाँधीवाद, जो ग्राम्य कुटीर एवं लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने से संभव है। आवश्यकता है चीन तथा जापान की भांति लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना की जाकर, उद्यमिता, कौशल विकास, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप को इन राष्ट्रों की भांति आरंभ करना होगा।

संदर्भ :

1. दत एवं सुंदश्य, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्करण, एस. चंद प्रा. लिमिटेड दिल्ली, 2019
2. पुरी एवं मिश्र, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्करण, हिमालय पब्लिकेशन मुबंई, 2020
3. अग्रवाल एस एन, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश बुक डिपो जयपुर, 2019

❖ ❖ ❖